माननीय जे.जे. एस. डी. अग्रवाल और जे.जे. एन. के. सोढ़ी समक्ष।

कंवरजीत सिंह ढिल्लों,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरदयाल सिंह ढिल्लों और अन्य-प्रतिवादी।

एल.पी.ए. 1991 का 854

1 दिसम्बर, 1993.

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925-धारा 222, 283 और 300- प्रोबेट कोर्ट के कार्य-केवल यह देखना है कि वसीयतकर्ता द्वारा बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के, स्वस्थ मन से वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया है।

यह माना जाता है कि यह अब तक अच्छी तरह से तय हो चुका है कि प्रोबेट कोर्ट का कार्य यह देखना है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत वास्तव में बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के एक स्वस्थ मन की स्थिति में निष्पादित की गई है और इसे विधिवत सत्यापित किया गया है। ऐसी अदालत यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं है कि वसीयतकर्ता के पास अपनी इच्छा से निपटान करने की शक्ति थी या नहीं। यह प्रोबेट का कार्य भी नहीं है और न ही न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करेगा कि क्या वसीयत द्वारा निपटाई गई संपत्ति वसीयतकर्ता की संयुक्त, पैतृक संपत्ति या स्व-अर्जित संपत्ति थी या यह पता लगाने के लिए कि क्या कुछ संपत्ति की वसीयत करने वाले व्यक्ति का भी उसी पर स्वामित्व था। प्रोबेट कोर्ट को यह भी तय नहीं करना चाहिए कि संपत्ति में लाभकारी रूप से रुचि रखने वाले व्यक्ति कौन हैं और यह सवाल कि वसीयत अच्छी है या बुरी, उसके डोमेन/दायरे में नहीं है।

(पैरा 7)

वसीयत का सबूत - वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने का दायित्व उसे प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति पर होता है।

माना गया कि किसी वसीयत के निष्पादन को साबित करने का दायित्व हर मामले में उसे प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति पर होता है और उसे न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार प्रतिपादित दस्तावेज एक स्वतंत्र और सक्षम वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है। यदि इस संबंध में निष्पक्ष एवं संतोषजनक साक्ष्य रिकार्ड पर लाया गया है तो प्रस्तावक के पक्ष में निष्कर्ष उचित होगा। हालाँकि, एक अन्य नियम यह है कि यदि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो न्यायालय के संदेह को उत्तेजित करती हैं और चाहे उनकी प्रकृति कुछ भी हो, तो यह उन लोगों पर निर्भर करता है जो इस तरह के संदेह को दूर करने के लिए वसीयत का प्रतिपादन करते हैं और इस तथ्य को साबित करते हैं कि वसीयतकर्ता वसीयत की सामग्री को जानता था। ऐसा केवल वहीं होता है जहां ऐसा किया जाता है कि जिम्मेदारी उन लोगों पर आ जाती है जो प्रस्तावक के मामले को विस्थापित करने के लिए धोखाधड़ी या किसी भी चीज़ के अनुचित प्रभाव को साबित करने की इच्छा का विरोध करते हैं।

(पैरा 7)

वसीयत—संदिग्ध परिस्थितियाँ—मृतक ने तलाकशुदा बेटी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, भले ही वह अपने जीवनकाल के दौरान तलाकशुदा थी—बच्चों वाले बेटे को छोड़कर पूरी संपत्ति कुंवारे बेटे के लिए छोड़ दी गई। माना गया कि ये तथ्य संदिग्ध परिस्थितियाँ नहीं हैं।

तर्क यह है कि सामान्य प्रक्रिया में संपत्ति उन बेटों को दी जानी चाहिए जिनके बच्चे थे। हमारी राय में ये शायद ही कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं और हरदयाल सिंह ढिल्लों द्वारा प्रतिपादित वसीयत का निष्पादन वर्तमान मामले की परिस्थितियों में विधिवत साबित हुआ है।

(पैरा 9)

अपीलकर्ता की ओर से वकील एस. खोजी।

प्रतिवादियों की ओर से एम.एस. खैरा, वरिष्ठ अधिवक्ता और के.एस. बख्शी, अधिवक्ता।

न्याय

एन.के. सोढ़ी, जे.

A. लेटर्स पेटेंट के खंड X के तहत यह अपील एक विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत उन्होंने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 276 के तहत प्रत्यर्थी हरद्याल सिंह ढिल्लों द्वारा दायर याचिका को मंजूरी दी थी। 1925 (संक्षेप में, 'अधिनियम') प्रोबेट के अनुदान के लिए।अपील के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्यों पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए।

B. कृपाल सिंह ढिल्लों सहायक निदेशक उद्योग, पंजाब के रूप में सेवानिवृत्त हुए और 31 अक्टूबर, 1979 को लगभग 67 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।मृत्यु के समय उनके पास निम्नलिखित संपत्तियाँ थीं:-

(i) चंडीगढ़ में घर संख्या 148, सेक्टर 27-एः

(i) उनके पैतृक गांव तलवंडी अब्दर, तहसील और जिला जालंधर में एक ट्यूबवेल के अलावा 48 कनाल 10 मरले की कृषि भूमि और एक खाली आवासीय स्थल; और

(ii)2 रुपये की जमा राशि। 20, 000 और रु। कुछ अन्य चल संपत्ति के अलावा निजी कंपनियों के साथ 10,000।

वह अपने पीछे अपनी विधवा के अलावा तीन बेटे और दो बेटियां छोड़ गए हैं। प्रतिवादी हरदयाल सिंह ढिल्लों, जो उनके सबसे बड़े बेटे हैं और कुंवारे हैं, ने 22 जुलाई, 1978 की वसीयत के संबंध में प्रोबेट देने के लिए अधिनियम की धारा 276/278 के तहत एक याचिका दायर की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उनके पिता द्वारा देर से छोड़ी गई थी। सरदार कृपाल सिंह ढिल्लों ने अपनी पूरी संपत्ति याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत कर दी। वसीयत की मूल प्रति याचिका के साथ संलग्न थी। आम जनता के अलावा वसीयतकर्ता की विधवा और उसके अन्य बच्चों को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था।

A. जारी किए गए नोटिस के जवाब में, कंवरजीत सिंह ढिल्लों-अपीलकर्ता ने याचिका का विरोध किया, अपने लिखित बयान में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किरपाल सिंह ढिल्लों ने 22 जुलाई, 1978 की वसीयत पर कभी हस्ताक्षर किए या निष्पादित किए। यह दलील दी गई कि वसीयत हरदयाल सिंह ढिल्लों द्वारा प्रस्तावित है, प्रतिवादी, एक जाली दस्तावेज़ था और पूरी तरह से अप्राकृतिक था। अपीलकर्ता के अनुसार वसीयत में यह नहीं बताया गया था कि इसे कहां

निष्पादित किया गया था और जिन गवाहों ने वसीयत को प्रमाणित किया था, वे न तो वसीयतकर्ता से संबंधित थे और न ही उस इलाके के निवासी थे जहां वसीयतकर्ता रहता था। अपीलकर्ता ने आगे दलील दी कि हरदयाल सिंह ढिल्लों अपनी सेवा के सिलसिले में चंडीगढ़ के बाहर विभिन्न स्टेशनों पर तैनात रहे और इसलिए, वह अपने दिवंगत पिता की सेवा नहीं कर सके और इसके विपरीत अपीलकर्ता जो राजपुरा में तैनात रहा वह अपने पिता के साथ रहता था और वसीयतकर्ता की सेवा करता था। . यह भी आरोप लगाया गया कि मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पैतृक थी।

B. अपने अलग लिखित बयान में मृतक की पत्नी और उनकी बेटियों (अपीलकर्ता की बहनों) ने हरदयाल सिंह ढिल्लों के दावे को स्वीकार किया और कहा कि उन्हें उनके पक्ष में प्रोबेट देने पर कोई आपत्ति नहीं थी।

C. रद्याल सिंह ढिल्लों ने एक प्रतिकृति दायर करके अपीलकर्ता के कथनों का खंडन किया जिसमें यह दलील दी गई थी कि विचाराधीन संपत्ति वसीयतकर्ता की स्व-अर्जित संपत्ति थी।

पक्षों की दलीलों ने निम्नलिखित दो मुद्दों को जन्म दिया:—

C..1.क्या वसीयत दिनांक 22 जुलाई 1978 मृतक सरदार कृपाल सिंह ढिल्लों का विधिवत और कानूनी रूप से निष्पादित अंतिम वसीयतनामा है? ओपीपी

C..2.क्या प्रत्यर्थी-6 के लिखित कथन की अतिरिक्त दलीलों में बताए गए तथ्यों पर प्रोबेट/प्रशासन का पत्र अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी है? ओपीआर।

A. पक्षों द्वारा दिए गए सबूतों की जांच करने और उनके वकील द्वारा दिए गए संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने 5 अप्रैल, 1991 के अपने आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के पक्ष में दोनों मुद्दों का फैसला किया और परिणामस्वरूप याचिका को स्वीकार कर लिया। मांगे गए प्रोबेट को जारी करने का निर्देश दिया गया। कंवरजीत सिंह ढिल्लों, जिन्होंने अकेले ही याचिका का विरोध किया था, अपील में आये हैं।

B. हमने पक्षों के वकील को विस्तार से सुना है। यह अब तक अच्छी तरह से तय हो चुका है कि प्रोबेट कोर्ट का कार्य यह देखना है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत वास्तव में बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के मन की एक स्वस्थ स्थिति में निष्पादित की गई है और इसे विधिवत सत्यापित किया गया है। ऐसे न्यायालय के लिए यह निर्धारित करना सक्षम नहीं है कि वसीयतकर्ता के पास उस संपत्ति का निपटान करने की शक्ति थी या नहीं, जिसे वह अपनी वसीयत द्वारा निपटान करना चाहता है। प्रोबेट कोर्ट का कार्य संपत्ति के स्वामित्व के प्रश्नों को निर्धारित करना भी नहीं है और न ही कोर्ट इस सवाल पर जाएगा कि वसीयत द्वारा निपटाई गई संपत्ति संयुक्त पैतृक संपत्ति थी या वसीयतकर्ता की स्व-अर्जित संपत्ति थी या यह पता लगाना कि क्या यह वसीयतकर्ता की संपत्ति है या यह पता लगाने के लिए कि क्या कुछ संपत्ति की वसीयत करने वाले व्यक्ति के पास उस पर स्वामित्व था। प्रोबेट कोर्ट को यह भी तय नहीं करना चाहिए कि संपत्ति में लाभकारी हित रखने वाले कौन से व्यक्ति हैं और यह सवाल कि वसीयत अच्छी है या बुरी, उसके डोमेन/दायरे में नहीं है। इस तथ्य को कहने का कोई लाभ नहीं है कि किसी वसीयत के क्रियान्वयन को साबित करने का दायित्व हर मामले में उसे प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति पर ही होता है और उसे न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करना होगा कि इस प्रकार प्रतिपादित दस्तावेज एक स्वतंत्र और सक्षम वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है। . यदि इस संबंध में निष्पक्ष एवं संतोषजनक साक्ष्य रिकार्ड पर

लाया गया है तो प्रस्तावक के पक्ष में निष्कर्ष उचित होगा। हालाँकि, एक अन्य नियम यह है कि यदि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो न्यायालय के संदेह को उत्तेजित करती हैं और चाहे उनकी प्रकृति कुछ भी हो, यह उन लोगों पर निर्भर करता है जो वसीयत को प्रतिपादित करते हैं और इस तरह के संदेह को दूर करते हैं और इस तथ्य को साबित करते हैं कि वसीयतकर्ता वसीयत की सामग्री को जानता था। केवल जहां ऐसा किया जाता है वहां वसीयत का विरोध करने वालों पर धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव या जो कुछ भी वे प्रस्तावक के मामले को विस्थापित करने पर भरोसा करते हैं उसे साबित करने का दायित्व स्थानांतरित हो जाता है।

C. वर्तमान मामले में, विल एक्ज़िबिट PW3/2 एक अपंजीकृत दस्तावेज़ है जो 2 पृष्ठों पर टाइप-लिखा हुआ है। दोनों पेजों पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर हैं। इसे मन्ना सिंह के पुत्र कश्मीर सिंह और गंगा सिंह के पुत्र सर्व नंदन सिंह ने प्रमाणित किया है. याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने प्रमाणित करने वाले दोनों गवाहों से पूछताछ की। पीडब्लू 4 के रूप में पेश हुए सर्व नंदन सिंह ने कहा कि उन्होंने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में एक प्रमाणित गवाह के रूप में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे और दूसरे गवाह कश्मीर सिंह ने भी उनकी उपस्थिति में और वसीयतकर्ता की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए थे और कहा कि वसीयतकर्ता ने उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये थे। इस गवाह के अनुसार, वसीयत चमन लाई नाम के एक टाइपिस्ट ने टाइप की थी जो किसी कंपनी में काम करता था और उसे इस काम के लिए बुलाया गया था। अन्य प्रमाणित गवाह कश्मीर सिंह-पीडब्लू5 का बयान भी इसी आशय का है। दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने मामलों के समर्थन में हस्तलेखन विशेषज्ञों को पेश किया गया। हालाँकि, दोनों ने कहा है कि संबंधित वसीयत पर वसीयतकर्ता कृपाल सिंह ढिल्लों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने वसीयत पर उसके हस्ताक्षरों की तुलना पेंशन भुगतान आदेश प्रदर्शनी पीडब्लू2/1 में मौजूद वसीयतकर्ता के स्वीकृत हस्ताक्षरों से की थी, जो भारतीय

स्टेट बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़ के रिकॉर्ड से तैयार किए गए थे, जहां से वसीयतकर्ता अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा था। . हरदयाल सिंह ढिल्लों-याचिकाकर्ता प्रतिवादी, जो वसीयतकर्ता का सबसे बड़ा बेटा है, ने वसीयत प्रदर्शनी PW3/2 पर अपने पिता के हस्ताक्षरों की भी पहचान की। उन्होंने पीडब्लू 3 के रूप में पेश होते हुए यह भी कहा कि उनके पिता अंत तक अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ दिमाग वाले थे और वास्तव में जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन वह व्यक्तिगत रूप से गए थे और बैंक से अपनी अंतिम पेंशन प्राप्त की थी। बाद में दिन में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा कि उनके भाई कंवरजीत सिंह ढिल्लों ने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की थी और उनके पिता इस बात से नाखुश थे। गवाह के अनुसार, कंवरजीत सिंह ढिल्लों के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तनावपूर्ण संबंध थे, जिनके साथ उनका कई मौकों पर झगड़ा होता था। श्रीमती किरपाल सिंह ढिल्लों की विधवा सुरजीत कौर भी हरदयाल सिंह ढिल्लों के संस्करण का समर्थन करने के लिए गवाह बॉक्स में उपस्थित हुईं। उन्होंने भी कहा कि उनके पति अंत तक स्वस्थ थे और सुबह अपनी पेंशन लेने के बाद दोपहर करीब एक बजे उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा कि वसीयतकर्ता के अपीलकर्ता कंवरजीत सिंह ढिल्लों के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। उनके अनुसार, अपीलकर्ता उनके और उनके पति के साथ लड़ता था और उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, जिससे उन्हें और उनके पति को अत्यधिक मानसिक पीड़ा और पीड़ा होती थी। उन्होंने यह भी कहा कि कंवरजीत सिंह ढिल्लों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी की थी और वे उनकी शादी में शामिल नहीं हुए थे। इन सभी गवाहों के बयानों से, विद्वान न्यायाधीश ने, हमारी राय में, सही निष्कर्ष निकाला कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय उसका दिमाग शांत था और उसने प्रश्नगत वसीयत को वैध रूप से क्रियान्वित किया था। रिकॉर्ड पर खुद अपीलकर्ता के बयान के अलावा कुछ भी नहीं है कि वसीयत के निष्पादन के समय वसीयतकर्ता अस्वस्थ था और वह

स्वस्थ्य नहीं था। विद्वान न्यायाधीश भी अपीलकर्ता के बयान पर भरोसा न करने में सही थे क्योंकि हमारी राय में, उन्होंने सच्चाई नहीं बताई है और इच्छुक गवाह थे। उनके अनुसार, उनके माता-पिता के साथ उनके संबंध सामान्य थे और उन्होंने अपने माता-पिता की जानकारी और सहमति से शादी की थी। वह अपनी ही मां का खंडन करता है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह उस पर विश्वास न करे। दरअसल, वसीयतकर्ता का पूरा परिवार हरदयाल सिंह ढिल्लों के पक्ष में है और मां ने अपीलकर्ता के खिलाफ गवाही दी है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि किरपाल सिंह ढिल्लों अपने सबसे छोटे बेटे, जो अपीलकर्ता है, से नाखुश रहे होंगे और यही कारण है कि उन्होंने अपनी संपत्ति का एक भी हिस्सा उसे नहीं दिया था। जैसा कि वसीयत में कहा गया है कि वसीयतकर्ता ने पहले ही अपीलकर्ता के पक्ष में गांव तलवंडी अब्दार, तहसील और जिला जालंधर में 5 एकड़ जमीन उपहार के रूप में हस्तांतरित कर दी थी और चूंकि अपीलकर्ता ने वसीयतकर्ता को अत्यधिक पीड़ा, पीड़ा और पीड़ा पहुंचाई थी इसीलिए वह अपनी संपत्ति का कोई भी हिस्सा उसे नहीं देना चाहता था।

D. अपीलकर्ता के वकील ने तब तर्क दिया कि किसी भी मामले में वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई थी क्योंकि मृतक ने अपनी तलाकशुदा बेटी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था, भले ही वह अपने जीवनकाल के दौरान तलाकशुदा थी। यह भी बताया गया कि वसीयतकर्ता जैसे जाट सिख की इच्छा होती है कि उसका परिवार उसके बाद भी जारी रहे और इसलिए, सामान्य स्थिति में वह अपनी संपत्ति हरदयाल सिंह ढिल्लों के पक्ष में नहीं दे सकता था जो कुंवारा था। तर्क यह है कि सामान्य स्थिति में संपत्ति उन बेटों को दी जानी चाहिए जिनके बच्चे हों। हमारी राय में, ये शायद ही कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं और हरदयाल सिंह ढिल्लों द्वारा प्रतिपादित वसीयत का निष्पादन वर्तमान मामले की परिस्थितियों में विधिवत साबित हुआ है। तदनुसार, हम विद्वान एकल

न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हैं और अपीलकर्ता के खिलाफ दोनों मुद्दों पर फैसला करते हैं।

E. परिणामस्वरूप, अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा